बी०सी०सी०एल० खानों में गैर-सरकारी ठेकेदारों को हटाया जाना

*5. **श्री राम अवधेश सिंह :** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा विभाग ने गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा राजकोष की लूट को रोकने के लिए बी०सी०सी०एल० खानों में कोयला परिवहन, रेत की आपूर्ति, परिवहन द्वारा पेयजल की आपूर्ति आदि जैसे सभी कार्य करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उस निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस बारे में एक नीति संबंधी निर्णय पहले से ही विद्यमान है कि जहां तक संभव हो, स्थायी तथा बारहमासी प्रकृति के कार्यों को केवल विभागीय आधार पर कराया जाए और संविदाएं केवल तदर्थ तथा आवर्तक प्रकृति के आपातिक कार्यों के लिए दी जाएं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के संबंध में प्राप्त की गई विभागीय उपलब्धि की प्रतिशतता को नीचे दिया गया है :-

(1) कोयला का परिवहन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरीज में कोयले का लगभग 84 प्रतिशत आन्तरिक परिवहन कंपनी के अपने नेटवर्क परिवहन के माध्यम से किया जाता है; अन्य 3 प्रतिशत परिवहन सहकारी समितियों के माध्यम से और बकाया निजी संविदाकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

(2) रेत का परिवहन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए भराई के लिए रेत तथा अन्य प्रयोजनों से रेत की आवश्यकता प्रतिवर्ष 3 मिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। इसमें से लगभग 19 प्रतिशत रेत का परिवहन कंपनी के ट्रकों तथा ग्रहीता रोपवेज; 17.50 प्रतिशत रेत का परिवहन सहकारी समितियों द्वारा तथा बकाया 63.50 प्रतिशत का परिवहन निजी संविदाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। रेत के परिवहन को बड़े पैमाने पर विभागीयकृत करने के मामले को विभिन्न कारणों से व्यवहारिक तथा किफायती नहीं पाया गया है।

(3) पेय जल की आपूर्ति

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पास अपनी एकीकृत जल आपूर्ति [illegible] के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है। किन्तु अभी-कभी अत्यधिक गर्मी के मौसम में अत्यधिक जल की मांग में वृद्धि हो जाती है। उस समय संविदा के आधार पर निजी जल के टैंकरों द्वारा जल की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। किन्तु इस मद पर अधिक व्यय नहीं आया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वर्ष 1988-89 के दौरान इस मद पर केवल लगभग 20 लाख रुपए की राशि खर्च की चूंकि इस प्रकार का कार्य पूर्णतः मौसमी तथा तदर्थ प्रकृति का है अतः इसे पूरी तरह से विभागीयकृत करना संभव नहीं है।

Price Decontrol on Drugs

*9. SHRI DHULESHWAR MEENA:
DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kelkar Committee has recommended price decontrol on drugs having sales turnover of rupees fifty lac or less;

(b) if so, how many of the drugs are still in the Drugs Price

Control Order, 1987 in spite of their sales turnover being less than rupee fifty lac;

(c) whether it is also a fact that a number of drugs which are identically placed are outside the price control; and

(d) if so, what corrective steps have been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (d) The Kelkar Committee, in its Supplementary Report (Copies of which are already available in the Parliament Library) has made observations/recommendations regarding exclusion of bulk drugs, under DPCO, 1987, on the basis of low turnover, of less than Rs. 50 lakhs per annum. The Government have yet to take a final decision on the recommendations in this regard.

इलाहाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठकें

*11. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से मार्च, 1989 की अवधि के दौरान इलाहाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या तीन महीनों के दौरान एक भी बैठक न करना सरकारी आदेशों का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) सरकार ने इस चूक के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) इलाहाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति की पिछली बैठक 31.12.88 को संपन्न हुई थी। तदुपरांत मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली तिमाही की बैठक 20.4.89 को हुई।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Direct Telephone Link with Foreign Countries

*12. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any plan to provide foreign visitors with the facilities to call their home countries through direct telephone links;

(b) if so, by when the "Home Country direct" scheme is likely to be launched; and

(c) which countries are proposed to be covered by this scheme?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BIR BAHADUR SINGH) (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Setting up of industries in the Rayalaseema District of Andhra Pradesh

*14. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is negligible growth of industry in Rayalaseema District of Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details of industries set up in this district so far and licences issued by the Central Government?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Under the provisions of